

Gov. 7 What is the difference between governance and management ?

प्रश्न ७. “व्यवस्थापन” और “प्रशासन” में क्या फर्क है ?

- अच्छे बोर्ड को संस्था के कार्य में रुची होती है ।
- संस्था के हेतू के बारे में वो वचनबद्ध होते है ।
- उनके पास होशियारी और क्षमता होती है ।
- समाज और अन्य हितसंबंधी उनका आदर करते है ।
- बोर्ड में ‘विकास करने की’ क्षमता होनी चाहिये ।
- बदलते हुए समाज में बदलती हुई और नयी समस्याओं के बारे में संवेदनशील होना ।
- बाकी लोगों के साथ मिलजूलकर कार्य करने की क्षमता ।
- खुदपर विश्वास होना और कार्यकर्ताओं के साथ समानता का व्यवहार ।
- मतभिन्नता होने के कार्यकर्ताओं के और अन्य सदस्यों के अधिकार का स्वीकार करना ।
- अगर बहुमत आप के विरुद्ध है तो सही तरीके से पद छोडना ।
- साधन इकट्ठा करना और उसका सही उपयोग करना ।
- बोर्ड की भूमिका प्रशासन की होनी चाहिये । व्यवस्थापन की नहीं ।

प्रशासन संस्था के कार्य को विस्तृत स्वरूप से जुडा होता है और व्यवस्थापन दैनंदिन कार्य में सुविधा लाने का काम करता है । नियम बनाना, निधी जमा करना, नेतृत्व करना, अंतिम हेतू सुनिश्चित करना और इस दिशा में कार्य करने को बढावा देना यह बोर्ड का काम है । लेकिन नियमों को अमल में लाना बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं है । कार्यपद्धती निश्चित करना बोर्ड की जिम्मेदारी है और उसे अमल में लाना व्यवस्थापन की जिम्मेदारी है ।

बोर्ड का काम प्रशासन में जुडा है लेकिन मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कार्यकर्ता व्यवस्थापन के हिस्से है । प्रशासन उत्तरदायित्व और पारदर्शकता से जुडा है । स्वनियंत्रण और संस्था चलाना प्रशासन के हिस्से है । अपने दाता, लाभार्थी, कार्यकर्ता, सरकार और अन्य हितसंबंधीओं की तरफ उत्तरदायित्व ये प्रशासन का हिस्सा है । पारदर्शकता मतलब स्पष्टता है । स्वनियंत्रण याने खुद पर नियंत्रण रखना है । संस्था चलाना इसका मतलब है संस्था चलती रहे इसलिये निधी इकट्ठा करना । आरटीआय - राइट टू इन्फर्मेशन अॅक्ट सरकारी संस्थाओं को लागू होता है । अगर आपकी संस्था सरकारी अनुदान लेती है तो आप आरटीआय की कक्षा में आते है ।

किसी भी संस्था जिसे एक करोड़ से ज्यादा चंदा मिलता है वो सरकारी अनुदान प्राप्त संस्था मानी जाती है ।

आप की संस्था का व्यवहार कितनी सीमा तक पारदर्शी होगा इसका निर्णय आपको ही लेना है । आप वेबसाइट माध्यम से कौनसी जानकारी देना चाहते है ये तय करना होगा । कानूनी तौर पर जो जानकारी देने की जरूरत नहीं है ऐसी जानकारी आप देना चाहोगे या नहीं ? कानूनन आपको ऑडीटेड अकाउंट्स, इनकम और एक्सपेंडीचर स्टेटमेंट, बॅलन्स शीट देना जरूरी है । आप मुख्य कार्यकारी अधिकारी को कितनी तनखाह देते हो ये वेबसाइट पे बताना जरूरी नहीं है । ट्रॅव्हल्स पे कितना खर्च होता है, डोनेशन कहा से मिलता है यह भी बताना जरूरी नहीं है । ये सब पारदर्शकता से जुड़े हुए मुद्दे है । कानूनन जिम्मेदारी से ज्यादा जिम्मेदार होना ये प्रशासन है और जरूरत से ज्यादा जानकारी देना ये पारदर्शकता है ।